**श्री मोहम्मद अमीन** : मेरे सवाल का पार्ट बी यह है कि पश्चिमी बंगाल के बहुत सारे मामलात बरसों से पड़े हुए हैं। उनका कोई उपाय नहीं हो रहा है। इसलिए पश्चिमी बंगाल की सरकार ने यह दरख्वास्त की है कि कलकत्ता में इसकी एक बैंच खोल दें। क्या मन्त्री जी इस पर गौर करेंगे ?

**प्रो० मधु दंडवते** : सभापति जी, कलकत्ता में शाखा शुरु करने के सिलसिले में मैं अभी आश्वासन नहीं दे सकता हूं लेकिन उसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे। जहां तक बी०आई०एफ०आर० का कार्य क्षेत्र है उसकी सीमा निश्चित की गई है। दिक्कत इतनी है कि जो प्रावधान तैयार किये गये हैं, उन पर अमल ठीक से नहीं होता है. मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि उनको अमल में लाने के लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाएगी।

**श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल** : सभापति जी, जीमार कम्पनियों को इन के पास थोपा जाता है उस में कई कम्पनियां रिवाइव हो सकती हैं लेकिन जो बैंकों के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर बोर्ड में जाते हैं उन लोगों का अपना इंट्रेस्ट होता है वह भी उस में से कुछ कमाते हैं। उनका इंट्रेस्ट न चला जाए इसलिए वह उस इंडस्ट्री को रिवाइव नहीं होने देते हैं। इसके बारे में आप क्या करेंगे, यह मेरा सवाल है ?

**प्रो० मधु दंडवते** : सभापति जी, यदि माननीय सदस्य विशेष अपवादों के बारे में वह जानकारी देंगे जो उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेंगे।

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTERJEE: Mr. Chairman, Sir, may I know from the hon. Minister how long it takes to dispose of the cases? I know that many cases remain pending with the BIFR for more than two or three years.

PROF. MADHU DANDAVATE: There are many cases which have actually been cleared within a year. But I agree that there are more than a dozen cases which remain pending for more than three years. It will be our effort to see that they are quickly expedited. They have been taking a long time even in regard to the cases which are to be wound up. We saw to it that the decision was taken expeditiously. In the matter of those cases which are still pending, we will ensure that there is no further delay.

**Economic and other aid from U.S.A.**

*145. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the extent of economic and other aid sought by Central Government from the United States for the ensuing year;

(b) what is the amount of aid granted in response thereto; and

(c) how does it compare with the US aid being given to Pakistan, Bangladesh and to other developing countries in the sub-continent?

THE FINANCE MINISTER (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) The Government of India does not make any request for a specific amount of aid from the US Government.

(b) and (c) As per the information furnished by our Embassy in Washington the foreign assistance allocation made by the US Government for US fiscal year 1990 (October, 1989 to September, 1990) for India and other countries in the sub-continent is as follows:

(in US dollars million)

| | India | Pakistan | Bangladesh | Sri Lanka | Nepal |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) Development Assistance | 22.473 | 43.000 | 52.500 | 18.000 | 12.393 |
| (ii) PL-480 Title II . . | 83.204 | 80.000 | 77.460 | 16.844 | 2.160 |
| (iii) Economic Support Fund | .. | 229.011 | .. | .. | .. |
| (iv) Foreign Military Financing Grant . . | .. | 229.011 | .. | .. | .. |
| (v) International Military Education & Training . . . . | 0.229 | 0.911 | 0.299 | 0.159 | 0.100 |
| | 105.906 | 581.933 | 130.259 | 35.003 | 14.653 |

**डा० रत्नाकर पाण्डेय** : महामहिम सभापति जी, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका और नेपाल को अक्टूबर 1989 से सितम्बर 1990 तक जो सहायता राशि आबंटित की है उसका विवरण संलग्न है और इसमें 1059.06 लाख डालर भारत को मिला है, 5819.33 लाख डालर पाकिस्तान को मिला है, यहां तक कि बंगलादेश को अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता 1302.59 लाख डालर है । इसमें सबसे अधिक विभाजन जो किया है उसमें पी0एल0-480 में हमको 832.04 लाख डालर और पाकिस्तान को 800.00 लाख डालर मिले हैं । लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि विदेशी सैनिक वित्तपोषण अनुदान या फारेन मिलिट्री फाइनेंसिंग ग्रांट जो मिली है उसमें 2290.11 लाख डालर पाकिस्तान को मिले हैं लेकिन भारत और अन्य उपमहाद्वीपीय देशों को कुछ भी नहीं मिला है । यह बड़ी चिंता की बात है । पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाने की तैयारी, इस आर्थिक सहायता से अमेरिका कर रहा है, इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सीधे पंजाब और काश्मीर में जो जनहानि करा रहा है, आतंकवाद फैला रहा है उससे स्पष्ट है कि यह सारी धनराशि सैनिक सहायता पर खर्च की जा रही है और भारत के अहित में भारत में आतंक फैलाकर, अस्थिरता पैदा करने के लिए प्रयोग में लायी जा रही है । पाकिस्तान किस रूप में इस धनराशि को खर्च कर रहा है और भारत सरकार ने इस पर क्या चिंता अमेरिका को जताई है यह मैं जानना चाहूंगा ।

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, it is true that as far as India is concerned, we have got 105.906 million US dollars. That is the assistance. And Pakistan has received 581.933 million US dollars. But the matter of greater concern is the fact that for Economic support fund, we have no aid—it is zero—and as far as Pakistan is concerned, from United States of America they received an assistance of 229.011 million US dollars. And further, from Foreign Military Financing Grant, we have nil and they have

got 229.011 million US dollars. That means, out of 581.9 million US dollars aid, Pakistan has received only for Economic Support Fund and Foreign Military Financing Grant 458 million US dollars. It is a matter of great concern. The previous Government as well as the present Government has strongly expressed its concern and has repeatedly tried to point out to the United States of America that its assistance to Pakistan, specially for Foreign Military Financing Grant will be considered as a factor that will further create circumstances for India which will go against the interest of our country. We have already warned, but beyond that we cannot do anything more. But there is one more aspect. There is the question of Super 301. That is a matter of greater concern. When recently the United States of America found that Section 301 of US Trade Act provides enforcement of US rights and responses to certain foreign trade practices, in response to some of our policies, they have threatened to take up certain postures. And they claimed that they have been provoked by a number of factors like our equity share. We have decided that we should have better consideration regarding equity shares in high-tech and export. They also want that they should have entry into the insurance institutions, they should be able to have the insurance institutions. But since we have nationalised, this we are not going to have it. And we consider Super-301 as something which will be affront to our policies. We have expressed our opinion very clearly and emphatically.

**डा० रत्नाकर पाण्डेय** : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसमें उनकी चिंता है कि जो धनराशि सैनिक सहायता की अमरीका से पाकिस्तान को मिली है, वह भारत को अस्थिर करने में खर्च होगी ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस तरह की कोई चिंता और कोई प्रोटेस्ट अमरीकी सरकार के लिए किया है और किया है, तो वर्तमान भारत सरकार ने कब किया है ? मार्क सम्मेलन के मंच पर या और इंटरनेशनल मंच पर क्या इस तरह की कोई कार्यवाही की गई है ? भारत ने वहां क्या इस मामले को उठाया है और यदि नहीं उठाया है, तो क्यों नहीं उठाया है और उठाना चाहते हैं, तो आप क्या उपाय करना चाहते हैं ? अमरीकी सरकार को आपने क्या प्रोटेस्ट किये है और इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं और इंटरनेशनल जो हमारे मंच हैं, जिनका भारत सदस्य है, उस पर आप क्या करने जा रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं ?

PROF. MADHU DANDAVATE: We have taken a strong public position against the decisions on various occasions and the main elements of our stand are that we shall not negotiate under threat of retaliation inherent in the 301 provision, we cannot accept dictation from a foreign country on domestic economic policy. And, at the same time, we have pointed out that some of the issues raised by the USA have been on the agenda of such bodies as the Indo-U.S. Economic Sub-Commission and a dialogue could continue there if the threat of retaliation is lifted. We have told them very categorically. That means all other issues can be taken up provided you lift up this. Trade in services, trade related investment measures and trade related aspects of intellectual property rights are included in the agenda of the Uruguay round of multinational trade negotiations. By seeking concessions bilaterally in these areas the U.S. has put the multi-lateral forces in serious jeopardy and this has been communicated to them.

हमने साफ तरीके से उन्हें कहा है कि जो सवाल हमारे मल्टी-लेट्रली टाक्स में लेने की जरूरत है, वह अगर बाइलेट्रली आप टेबल में सेटल करने की कोशिश करेंगे, तो हम सबमिट नहीं करेंगे । इन इशूज को बाइलेट्रली हम कभी भी सैटल नहीं कर सकते ।

**डा० रत्नाकर पाण्डेय** : इस मामले को इंटरनेशनल मंच पर उठाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे सार्क या और संगठन हैं, जिनका भारत सदस्य है ? उस संदर्भ में भारत सरकार ने कुछ किया है या करने का विचार रखती है ?

**प्रो० मधु दंडवते** : यह फोरम नहीं है, जिस जगह हम यह सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अन्य फोरम में, जैसे मैंने कहा, हमने उनका पूरा इस्तेमाल किया है ।

**डा० रत्नाकर पाण्डेय** : विश्व जनमत बनाने के लिए पाकिस्तान अपना सैनिक उपनिवेश बना कर देश की राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए अमरीका पहल कर रहा है, इस संदर्भ में. . . . . **(व्यवधान)**

**श्री सभापति** : उन्होंने कहा ना कि यह सार्क में नहीं उठाया जा सकता है ।

**डा० रत्नाकर पाण्डेय** : आप इंटरनेशनल मंच पर क्या कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं ?

**प्रो० मधु दंडवते** : इस मामले में मैंने जो कुछ बताना था, वह साफ तरीके से बता दिया है । इससे आगे चल कर अगर कुछ आवश्यकता होगी, तो जरूर करेंगे ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: In this connection the Prime Minister went to Namibia.

SHRI ANAND SHARMA: I am very happy to hear from the hon. Minister that the Government will not accept unwarranted interference as far as our internal policies are concerned and linking that with the developmental assistance. But, Sir, the meagre developmental assistance which has been offered to India last year and the year before that, there has been a mischief in the USA and the people behind the mischief happen to be the forces which are working against the interests of this country. In the U.S. Congress for two successive years resolutions have been adopted linking the developmental assistance through India with internal issues and problems. The assistance which was offered was with a rider. The rider was the question of human rights, particularly in the province of Punjab. What has been the stand of the Government, (a) whether the Government will accept any developmental assistance with such riders, and (b) whether the amount of assistance being given to Pakistan, particularly the military assistance...and also the various statements made in this regard and, above all, the use of Super 301, to which the Finance Minister also made a reference, are considered by the Government as unfriendly acts or as friendly acts by the United States of America and as an impediment in the improvement of relations between the two countries.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, it has been the accepted national policy of the Government that whenever we accept aid, we do not accept it with any strings. There is no question of getting any assistance from the U.S.A., with any riders. We have not accepted it and we will never accept it in the future also.

*146. [*The Questioner (Shri Krishna Kumar Birla) was absent. For answer,* vide *Col.* 38 infra.]

*147. [*The Questioner (Shri Ghufran Azam) was absent. For answer.* vide *col.* 39 infra.]

**Restrictions of relatives of banking heads for dealings with financial institutions**

*148. SHRI J. P. JAVALI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there are any restrictions on the heads of banking institutions not to allow their close relatives from having dealings with the respective institutions and also with the beneficiary industrial concerns;